



कृषि विज्ञान केन्द्र, बोकारो (अटारी पटना जोन- IV) (बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके राँची)



केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं

माइक्रो इरिगेशन फंड (MIF)	- NABARD के तहत ₹5000 करोड़ के फंड स्थापित किये गए हैं - सूक्ष्म सिंचाई - NABARD द्वारा 3 % कम ब्याज दर पर राज्यों को ऋण प्रदान करना है
पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY)	- क्लस्टर मोडल लागू किया जाता है, जिसमें न्यूनतम 20 हेक्टेयर ज़मीन तथा प्रत्येक समूह में 20 किसान हो - प्रति हेक्टेयर ₹31500 की सहायता राज्यों को, जिसमें से ₹15000 किसान को DBT के माध्यम से दी जाती है
कृषि यंत्रीकरण के लिए उप-मिशन योजना	- स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कृषि यंत्रों का उपकरण बैंक स्थापित करना - उपकरण बैंक की स्थापना हेतु SHG को 80% अनुदान तथा 20% कृषक अंशदान पर दी जाएगी
कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE)	- VISTAAR - Apurva AI - Wadhwani-Krishi 24 into 7 - किसान कॉल सेंटर (KCC) - RAWE (Rural Agriculture Work Experience) - IMD (भारतीय मौसम विभाग) - NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) - eNAM (National Agriculture Market) - PM-KISAN मोबाइल ऐप - M-Kisan SMS पोर्टल
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	किसानों को ₹3 लाख तक का आसान और सस्ता ऋण मिलता है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज में 2-5% तक की छूट मिलती है, जिससे ब्याज दर घटकर 4% तक हो सकती है।
मिलेट मिशन योजना	मोटे अनाज (बाजरा, ज्वार, रागी) उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹3000 दिया जाता है।
प्रधान मंत्री कुसुम योजना	किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्पसेट 2HP मोटर- ₹5000, 3 HP मोटर- ₹7000, 5HP मोटर- ₹10000 में दिया जाता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)	किसानों को कृषि उपकरण 50% अनुदान पर तथा बीज 100% अनुदान पर दिये जाते हैं।
झारखंड किसान समृद्धि योजना	90% सब्सिडी पे सोलर पंप सेट दिया जाता है ₹1,80,000 का पम्पसेट में मात्र किसानों को ₹18,000 देने होते हैं।
बिरसा बीज उत्पादन, एवं फसल विस्तार योजना	खरीफ एवं रबी दोनों मौसमों में 50% अनुदान पर बीज लैप्स/ पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना	₹50,000 से लेकर ₹1,00,000 तक का ऋण माफ कर दी जाती है।